

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0



राजस्व अपील सं0 20/2024

निर्भयसिंह पुत्र जगराम जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील महवा जिला दौसा

...अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार महवा दिनांक 3.6.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम निर्भयसिंह प्रकरण संख्या 13/2020 अंतर्गत धारा 91 लैएड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत (अनुपस्थित)

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 30.4.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत ने नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.6.2020 जो कि प्रकरण सं0 13/2020 उनवानी सरकार बनाम निर्भयसिंह से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांत के उपस्थित नहीं होने से न्याय हित में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई।
3. मुताबिक अपील मीमो अपील के तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का ने अपीलांत के विरुद्ध एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार जी महवा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलांत अतिक्रमी निर्भयसिंह ने सम्वत 2077 फसल खरीफ में ग्राम रतनपुरा की राजकीय आसजी खसरा नम्बर 393 रकबा 0.95 है0 किस्म गै०मु० रास्ता भूमि से 0.01 है० के रकबे पर अनाधिकृत रूप से पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसील महवा ने अपीलांत को बिना कोई विधिवत सुनवाई व सबूत का मौका दिये ही निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलांत को भूमि से बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया व 50 गुणा शास्ति राशि कायम कर दी। पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट के आधार पर दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील पेश की जा रही है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा विधि विरुद्ध एवम तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। पटवारी हल्का ने अपीलांत के विरुद्ध गलत व मौके के विपरीत रास्ते पर अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट पेश की है, जबकि अपीलांत ने कोई रास्ता बन्द नहीं किया है। शिकायतकर्ता का रास्ता ही अलग है जो मकान में आने जाने का है। अपीलांत प्रार्थी का रास्ता भी अलग है। यह रास्ता गांव के आने जाने का रास्ता नहीं है तथा जो निर्माण करना बताया है वह भी पूर्व का किया हुआ निर्माण है पूर्वजो के समय का ही निर्माण है कोई नया निर्माण नहीं किया गया है, ना ही कोई रास्ता अपीलांत द्वारा बन्द किया गया है। तथा जो निर्माण पूर्व में पूर्वजो द्वारा किया गया है वह पंचायत से ईजाजद लेकर ही बनाया गया है अतः अपीलांत का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने गलत व मौके के विपरीत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अधिनस्थ नायब तहसीलदार ने जो निर्णय फरमाया है वह विधि विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं हैं ना ही इसका कोई हवाला ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है इसलिए भी बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलांत को अतिक्रमी मी नहीं माना जा सकता। प्रार्थी का पूर्व में भी कोई अतिक्रमण साबित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने

DW
जिला कलेक्टर, दौसा

अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को कानूनन सिविल कारावास की सजा करने का कोई अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का मौका भी नहीं दिया बिना रिपोर्ट प्रदर्शित हुए ही रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण ही नहीं किया जा सकता। इसलिए भी अधिनस्थ नायब तहसीलदार जी महवा का निर्णय निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है यह प्रकरण राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जी महवा दिनांक 3-06-2020 निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट बाद तामील अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी ने ग्राम रतनपुरा के राजकीय भूमि खसरा नंबर 393 गै0मु0 रास्ता पर पक्की दीवार बनाकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
5. प्रकरण में विवाद नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.6.2020 है जिसमें उनके द्वारा श्री निर्भय सिंह पुत्र जगराम को खसरा नंबर 393 रकबा 0.95 है भूमि में से 0.01 है पर अनाधिकृत रूप से पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये हैं।
6. प्रार्थी का कथन है कि यह आदेश प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये पारित किया गया है साथ ही यह रास्ता ग्राम के आने जाने का रास्ता नहीं है एवं जो निर्माण करना बताया गया है वह पूर्व का निर्माण किया हुआ है एवं पंचायत से इजाजत लेकर बनाया गया है।
7. जहाँ तक प्रश्न प्रार्थी को बिना सुनवाई के आदेश पारित करने के संबंध में है जिसमें हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट ने दिनांक 3.6.2020 को अपना जवाब प्रेषित किया गया है। यह तथ्य आदेशिका दिनांक 3.6.2020 से भी स्पष्ट होता है जिसमें अतिक्रमी की ओर से वकील उपस्थित होने एवं जवाब पेश करने का अंकन किया गया है। जहाँ तक प्रार्थी का यह कथन है कि यह गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है एवं दीवार का निर्माण पूर्व में ही करवा लिया गया था तो इस संबंध में उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी को किसी भी प्रकार से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की छूट प्रदान नहीं करते हैं। रास्ता एक सुखाचार है जो कि सामुदायिक संपत्ति है। जिस पर अतिचार करने से आम जन के सुखाचार में व्यवधान पैदा होता है एवं लडाईं झगडे एवं विवाद बढ़ते हैं। ऐसे में राजकीय अभिलेख में रिकार्डेड रास्ते पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण चाहे वह पुराना हो स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकरण में भी तहसीलदार द्वारा पटवारी से दो अलग-2 समय पर रिपोर्ट ली गई है एवं दोनों रिपोर्ट में (दिनांक 28.5.2020 एवं 2.6.2020) को उक्त खसरे पर अपीलांटका अतिक्रमण पाया गया।
8. जहाँ तक प्रार्थी का यह कथन है कि उक्त दीवार उनके पूर्वजों द्वारा पंचायत से इजाजत लेकर बनाई गई थी तो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं राजकीय भूमि जो कि रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित है पर दीवार बनाने की अनुमति ग्राम पंचायत को देने का अधिकार नहीं है। यदि इस प्रकार ऐसा कोई दस्तावेज

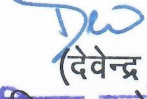


अस्तित्व में भी है तो वह शून्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2020 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



निर्णय आज दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयवधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा





(देवेन्द्र कुमार)

जिला कलेक्टर, दौसा